रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED NO. D222

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 14, 1966 (वैशाख 24, 1888)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 14, 1966 (VAISAKHA 24, 1888)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 27 अप्रैल 1966 तक प्रकाशित किये गये थे —

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 27th April 1966 —

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
69.	No 52-ITC(PN)/66, dated 22nd April, 1966	Ministry of Commerce	Import of (i) Dates [S No 21(bh)/IV], (ii) Medicinal Herds (Crude Drugs) (S No. 87-109-IV), (iii) Asafoetida [S. No 31 (b)/V] and other miscellaneous items from Iran for October, 1965—March, 1966, licensing period
70	No 51-ITC (PN)/66, dated 22nd April, 1966	-do-	U.S A I D Programme Chartering of Ocean Vessels and embargo on certain vessels for transport of AID—financed goods
71	No F.17/7/66-SR, dated 23rd April, 1966	Ministry of Home Affairs	Appointment of a commission to determine the actual boundaries of the Punjab and Haryana States
71A	सं० 17/7/66-एस० आर० दिनांक 23-4-66	गृह मंत्रालय	डाक आयोग की नियुक्ति जो कि पंजाब और हरियाना राज्यों की वास्तविक सीमाये निर्धारित करेगा ।
72	No 53-ITC (PN) 66, dated 25th April, 1966	Ministry of Commerce	Import of Capital goods and other items under National Defence Remittance Scheme
73	No 54-ITC (PN) 66, dated 26th April 1966	-do-	Import policy for Newsprint White Printing paper (excluding laid marked paper) which contains mechanical wood pulp amounting to not less than 70 per cent of the fibre contents S No. 44/V for the year April, 1966—March, 1967
74	No. 40/3/65-AR (P), dated 27th April, 1966	Ministry of Home Affairs.	Appointment of Shri Debabrata Mookerjee, M P. as a member of the Administrative Reforms Commission in place of Shri G S. Pathak.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची
(CONTENTS)

	पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों के संबंधित अधिसूचनाए ..	375
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरो की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाए	415
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और सकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं ..	421
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरो की नियुक्तियो, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाए ..	283
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितिओ की रिपोर्ट	

	पृष्ठ (Pages)
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	835
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii) (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1295
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	141
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	307
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	179
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	51
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	343
भाग VI—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	115
पूरक सं० 20—	
7 मई 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	683
16 अप्रैल 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े ..	695

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	375
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	415
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence	18
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	835
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1295
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	141
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	307
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	179
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	51
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	343
PART IV—Advertisement and Notices by Private Individuals and Private Bodies	115
SUPPLEMENT No. 20—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 7th May 1966	683
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 16th April	695

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 1966

तकनीकल परामर्श सेवाओं सम्बन्धी समिति

सं० उ० व ख० 4(9)2/66—योजना आयोग के दिनांक 9 फरवरी 1966 के संकल्प संख्या उ० व ख० 4(9)2/66 में गठित तकनीकल परामर्श सेवाओं संबंधी समिति के सदस्य श्री के० एल० घयी के स्वर्गवास होने पर, श्री घयी के स्थान पर श्री टी० स्वामिनाथन, सचिव, रक्षा सम्भरण विभाग को इसी समय से समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है ।

देवव्रत दास, अवर सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 1966

सं० 25/65—आई०टी०डी०—योजना आयोग के दिनांक 1 जून 1962 के संकल्प संख्या एफ० 13/39/62-प्रशासन-1 में गठित भारत और जापान के आर्थिक विकास सम्बन्धी अध्ययन समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार किया गया है :—

प्रो० वी० के० आर० वी० राव . .	अध्यक्ष
श्री लाल जी मेहरोत्रा . .	सदस्य
श्री रामनाथ ए० पोद्दार . .	सदस्य

योजना आयोग में प्रभाग के प्रमुख डा० डी० के० घोष, समिति के सचिव होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के प्रमुखों को भेज दी जाय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जाय ।

के० ए० पी० स्टीवेन्सन, संयुक्त सचिव

उद्योग मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 1966

सं० 34(4)/65-एल० इण्ड०-2—भारत सरकार ने कांच तथा चीनी-मिट्टी के उद्योग के लिए एक नामिका बनाने का निश्चय किया है । नामिका का कार्यकाल इस संकल्प की तिथि से 2 वर्षों का होगा और इसका गठन निम्न प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

1. डा० एस० आर० लेले,
 मैसर्स बोरोसिल ग्लास वर्क्स लि०, छोटानी एस्टेट्स, प्राक्टर रोड, ग्रान्ट रोड, बम्बई-7 ।

सदस्य

2. श्री जी० के० भगत,
 मैसर्स बंगाल पाटरीज़ लि० 45, तांगड़ा रोड, कलकत्ता-15 ।
3. श्री एम० के० गनपुले,
 मैसर्स परशुराम पोटरीज़ वर्क्स कं० लि०, वांकनेर (गुजरात) ।
4. श्री एच० एल० सोमानी,
 मैसर्स हिन्दुस्तान टाईफोई्स लि०, पोस्ट बाक्स नं० 990, कलकत्ता-1 ।
5. श्री ए० सम्बामूर्ति, निदेशक,
 गवर्नमेंट पोर्सलिन फैक्ट्री, बंगलौर-12 ।
6. श्री एस० के० बोस,
 भूतत्ववेत्ता (वरिष्ठ), जियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, 27, चौरंगी रोड, कलकत्ता-13 ।
7. श्री के० डी० शर्मा,
 वैज्ञानिक, सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता-32 ।
8. श्री बी० बी० सरकार,
 कृष्णा सिलीकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लि०, 6-इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-1 ।
9. श्री वी० आर० भिडे,
 मैसर्स कंगन प्राइवेट लि०, 208, लेडी जमशेदजी रोड, बम्बई-16 ।
10. श्री पी० सी० वार्ष्णेय,
 मैसर्स सेराइकेला ग्लास वर्क्स (प्रा०) लि०, कांद्रा (सिंघभूम) बिहार ।
11. श्री सी० जी० अमीन,
 डायरेक्टर (मैनुफैक्चरिंग), मैसर्स एलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज़, लि०, एलैम्बिक रोड, बड़ोदा ।
12. श्री के० एच० पारिख,
 महाप्रबन्धक, विभूति ग्लास फैक्टरी, रामनगर, वाराणसी (उ० प्र०) ।
13. विकास अधिकारी (सिरेमिक्स),
 तकनीकी विकास का महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली ।
14. श्री एस० आर० खन्ना, विकास अधिकारी (कांच),
 तकनीकी विकास का महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली । सदस्य-सचिव

2. नामिका के कार्य ये होंगे :—

(1) कच्चे माल की आवश्यकता का विस्तार में पता लगाना और कांच तथा चीनी-मिट्टी के उद्योगों के प्रतिमानित कच्चे माल के लिए अभिकरणों की स्थापना करने के लिए उपाय खोजना तथा कांच और चीनी मिट्टी उद्योगों की मशीनों/फालतू पुर्जों का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से उनकी आवश्यकता का पता लगाना ।

(2) ईंधन और कच्चे माल की बरबादी रोकने, अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने, किस्म में सुधार करने और लागत में कमी करने की दृष्टि से कार्यकुशलता बढ़ाने वाले प्रतिमानों के बारे में सुझाव देना ।

(3) स्थापित क्षमता का अधिक उपयोग किए जाने तथा उद्योग, विशेषकर कम कुशलता वाले एककों की कार्य-प्रणाली में सुधार करने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(4) निर्यात कार्यक्रम, विशेष रूप से उन वस्तुओं का, जिनकी फालतू क्षमता है, चलाने के लिए अत्यधिक प्रयास करना ।

(5) उन वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं की खोज करना जिनका उत्पादन सम्बद्ध उद्योगों द्वारा किया जा सकता है ।

(6) तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में निरन्तर विकास होता रहे, इसका सुनिश्चय करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना ।

(7) आयात किए जाने वाले कच्चे माल, फालतू पुर्जों तथा अन्य सबंधित उपकरणों की स्थापन वस्तुओं के लिए उपायों और साधनों के बारे में सुझाव देना ।

(8) उद्योग से सबंधित किसी भी अन्य ऐसे मामले में सलाह देना, जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार नामिका से जांच-पड़ताल करने और सलाह देने के प्रयोजन से ऐसा परामर्श देने के लिए उससे कहे ।

आदेश

आदेश दिया गया कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया गया कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

संकल्प

दिनांक 29 अप्रैल 1966

सं० 34(4)/65-एल० इण्ड०-2—भारत सरकार ने ऊष्म सह-उद्योग के लिए एक नामिका बनाने का निश्चय किया है । नामिका का कार्यकाल इस संकल्प की तारीख से दो वर्ष का होगा और इसका गठन निम्न प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

1. श्री डी० आर० सुब्रह्मण्यन,
महाप्रबन्धक,
मैसर्स बर्न एण्ड कं० लि०, 12, मिशन रो,
कलकत्ता-1 ।

सदस्य

2. डा० एस० पी० वर्मा,
औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

3 श्री जे० सी० बनर्जी,
वैज्ञानिक, सैन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरामिक इन्स्टीट्यूट
कलकत्ता-32 ।

4. डा० बी० एन० सिन्हा,
जियोलाजिस्ट (वरिष्ठ), जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया,
27, चौरंगी रोड, कलकत्ता-13 ।

5. श्री एम० सत्यपाल,
निदेशक (रसायन),
योजना आयोग, नई दिल्ली ।

6. डा० एस० एस० घोष,
मुख्य अधीक्षक (लोहा तथा इस्पात),
हिन्दुस्तान स्टील लि०, भिलाई इस्पात संयंत्र,
भिलाई (मध्य प्रदेश) ।

7. श्री के० पी० झुनझुन वाला,
मैसर्स उड़ीसा इंडस्ट्रीज लि०, ब्रारंग, जिला कटक,
उड़ीसा ।

8 श्री पी० आर० चाकी,
मैसर्स बेलपहाड़ रिफ्रैक्टरीज लि०, बेलपहाड़,
उड़ीसा ।

9 श्री एम० एच० डालमिया,
मैसर्स उड़ीसा सीमेंट लि०, राजगंगपुर,
उड़ीसा ।

10. श्री बी० एन० भास्कर
प्रबन्ध निदेशक,
मैसर्स दि ईश्वर इंडस्ट्रीज लि०, ईश्वर नगर,
नई दिल्ली ।

11. विकास अधिकारी (सिरामिक्स), सदस्य-सचिव
तकनीकी विकास का महानिदेशालय, उद्योग भवन,
नई दिल्ली ।

2 नामिका के कार्य ये होंगे —

(1) चौथी योजना के दौरान इस्पात उत्पादन के नमूने पर आधारित विभिन्न प्रकार की ऊष्म-सह वस्तुओं की मांग तथा अन्य उद्योगों की आवश्यकताओं के नमूने का विस्तार में पता लगाना ।

(2) आयातित कच्चे माल, फालतू पुर्जों तथा अन्य सम्बन्धित उपकरणों के स्थान पर देशी वस्तुओं के लिए सुझाव देना ।

(3) ईंधन तथा कच्चे माल की बरबादी रोकने, अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने, किस्म में सुधार करने और लागत में कमी करने की दृष्टि से कार्य-कुशलता बढ़ानेवाले प्रतिमानों के बारे में सुझाव देना ।

(4) उद्योग से सबंधित किसी भी अन्य ऐसे मामले में सलाह देना जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार नामिका से जांच-पड़ताल करने और सलाह देने के प्रयोजन से ऐसा परामर्श देने के लिए उससे कहे ।

(5) निर्यात कार्यक्रम चलाने के लिए विशेष रूप से कुछ किस्मों की उन ऊष्म-सह वस्तुओं का, जो इस्पात बनाने की कार्य-विधि में परिवर्तन हो जाने के कारण भारत में फालतू हो गई हैं (जैसे सिलिका ऊष्म-सह वस्तुएं), निर्यात करने के लिए उसे अत्यधिक प्रयत्न करना चाहिए ।

(6) व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए ऐसी उपयुक्त व्यवस्था करना जिससे तकनीकी व्यक्तियों को निरन्तर प्रशिक्षण मिलता रहे; तथा

(7) इसका पता लगाना कि कुछ किस्मों की ऊष्म-सह वस्तुओं की खपत में कमी या वृद्धि हो जाने के फल-स्वरूप वर्तमान निर्माण के क्षेत्र में कहां तक विविधता लाई जा सकती है ।

आदेश

आदेश दिया गया कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया गया कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित कराया जाए ।

आर० के० रंगन, उप-सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

कृषि विभाग

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

संस्ताव

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 1966

सं० एफ० 6-5/65–रिआर्ग (सी० सी०)/(एडमिन०)—भारत में कृषि शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रसार की स्थिति का पर्यवेक्षण करने के लिए 1959 में नियुक्त किये गये द्वितीय संयुक्त भारत-अमरीकी दल ने यह सिफारिश की थी कि यथेष्ठ समन्वय प्राप्त करने तथा केन्द्रीय कृषि अनुसंधान कार्यक्रम को सुगठित करने के लिये सब केन्द्रीय संस्थानों तथा जिन्स समितियों को पूर्ण रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकार में लाया जाए। इस सिफारिश का पूर्ण समर्थन 1963 में नियुक्त किये गये कृषि अनुसंधान पर्यवेक्षक दल ने भी किया। केन्द्रीय जिन्स समितियों द्वारा पिछले वर्षों में किये गये वास्तविक कार्य को दृष्टि में रखकर भारत सरकार ने उक्त सिफारिशों की जांच की है तथा यह निर्णय किया कि इन समितियों को समाप्त करके इनके अनुसंधान कार्य को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के साथ मिला दिया जाए तथा परिषद् का उपयुक्त पुनर्गठन करके इसे अधिक सुदृढ़ किया जाए जिससे कि परिषद् देश की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि के राष्ट्रीय कार्यक्रम का संचालन तथा विकास कर सके। तदनुसार 30 सितम्बर, 1965 को भारतीय केन्द्रीय मसाले और काजू समिति का विघटन किया गया तथा इसके अनुसंधान कार्य का भार 1 अक्तूबर, 1965 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने संभाल लिया।

2. समिति द्वारा किए जाने वाला विकास तथा विपणन कार्य भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। काजू विकास से संबंधित विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क बनाए रखने तथा उनकी सलाह का लाभ प्राप्त करते रहने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारतीय काजू विकास परिषद् बनाने का निश्चय किया है। प्रारम्भ में इस विकास परिषद् का गठन इस प्रकार होगा :—

1. **अध्यक्ष** — निदेशक, काजू विकास प्रादेशिक कार्यालय, (काजू विकास), कोझीकोडे।

2. **उपाध्यक्ष** — श्री सी० एम० जान, "चेरुकारा" पोस्ट · चेंगाचेरी, केरल राज्य।

3. **सदस्य गण :**

(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

(1) एक प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य के कृषि विभाग से निम्नलिखित सरकारों द्वारा मनोनीत :
- (1) केरल
- (2) मद्रास
- (3) मैसूर
- (4) आन्ध्र प्रदेश
- (5) उड़ीसा
- (6) पश्चिमी बंगाल
- (7) महाराष्ट्र
- (8) असम

(2) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि।

(3) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।

(4) महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अथवा उनके प्रतिनिधि।

(5) कृषि उत्पादन आयुक्त।

(6) अध्यक्ष, काजू निर्यात विकास परिषद्।

(ख) **उत्पादकों के प्रतिनिधि**

(1) श्री ए० बी० प्रभु, बी० एस० सी० (कृषि), एल० एल० बी०, सावंतवाडी जिला रत्नागिरी (महाराष्ट्र)

(2) श्री ओमियो कुमार दास, एम०एस०ए०, धेकिया-जुली, दरंग (असम)।

(3) श्री वी० बी० नारायण राव, वर्धा भवन, वर्धावरी स्ट्रीट, बरहामपुर (जिला गंजम), उड़ीसा राज्य।

(4) केरल राज्य से एक प्रतिनिधि।

(5) मैसूर राज्य से एक प्रतिनिधि।

(ग) **व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधि**

(1) श्री एस० एम० थाहा, मार्फत मुशेयर इन्डस्ट्रीज़ लि०, किलन, केरल राज्य।

(2) श्री वी० पी० वर्दे, मार्फत आर०आर० नाहर एण्ड कम्पनी, पो० बाक्स नं० 1498, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई।

(3) श्री सिराम राधाकृष्णय्या, अध्यक्ष, पालासा कैश्यु मैन्युफेक्चरर्ज एसोसियेशन, पलासा, जिला, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश।

(4) श्री विट्टलदास शैटी विट्टल, मंगलौर, जिला साउथ कनाडा, मैसूर।

(घ) **संसद के प्रतिनिधि**

(1) श्री चेरियन जे० कप्पेन, एम०पी०, 177, नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली।

(ङ) ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति, जिनको समय-समय पर सरकार मनोनीत करेगी, जो उन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनका परिषद् में कोई प्रतिनिधि नहीं है।

4. **सदस्य-सचिव** — खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) में काजू की फसल के कार्य से सम्बन्धित उप-सचिव अथवा अन्य कोई अधिकारी।

5. **प्रेक्षक :** (जो कि परिषद् के सदस्य तो नहीं होंगे परन्तु परिषद् के विचार-विमर्श में सहायतार्थ अनिवार्यतः उन्हें आमंत्रित किया जायेगा।)

(1) कृषि विपणन सलाहकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग)।

(2) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय से सम्बन्धित संयुक्त सचिव (वित्त)।

(3) अर्थ तथा सांख्यिकी सलाहकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग)।

(4) अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम।

(5) भारतीय रेलों का एक प्रतिनिधि।

3. परिषद एक सलाहकार संस्था होगी तथा उसके कार्य निम्नलिखित होंगे।

(1) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए काजू विकास के कार्यक्रमों पर समय-समय पर विचार करना।

(2) निर्धारित लक्ष्यांकों के संदर्भ में काजू विकास की प्रगति पर पुनरीक्षण तथा उस पर विचार करना।

(3) काजू विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं की प्रगति को, जहां कहीं आवश्यक हो, तीव्रतर करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।

(4) काजू विपणन तथा व्यापार की समस्याओं (मूल्य नीति निर्धारण सहित) का पुनरीक्षण एवम् उन पर विचार करना तथा उनमें सुधार के लिये सुझाव देना; और

(5) भारत सरकार द्वारा समय समय पर परिषद् को सौंपा जाने वाला कोई अन्य कार्य।

4. काजू उत्पादक क्षेत्रों के व्यापारिक तथा औद्योगिक महत्व के केन्द्रों में परिषद् समय-समय पर अपनी बैठक बुलाएगी तथा सरकार को अपनी सिफारिशें पेश करेगी।

आदेश

आदेश है कि इस संस्ताव की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्री मण्डल के सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जायें।

2. यह भी आदेश है कि यह संस्ताव भारतीय राजपत्र में जन-साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाये।

सं० 6–6/65 रीआर्ग० (सी० सी०) (एडमिन०)—भारत में कृषि शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रसार की स्थिति का पर्यवेक्षण करने के लिये 1959 में नियुक्त किये गये द्वितीय संयुक्त भारत-अमरीकी दल ने यह सिफारिश की थी कि यथेष्ठ समन्वय प्राप्त करने तथा केन्द्रीय कृषि अनुसंधान कार्यक्रम को सुगठित करने के लिये सब केन्द्रीय संस्थानों तथा जिस समितियों को पूर्ण रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकार में लाया जाय। इस सिफारिश का पूर्ण समर्थन 1963 में नियुक्त किए गए कृषि अनुसंधान पर्यवेक्षक दल ने भी किया। केन्द्रीय जिस समितियों द्वारा पिछले वर्ष में किए गए वास्तविक कार्य को दृष्टि में रखकर भारत सरकार ने उक्त सिफारिशों की जांच की है तथा यह निर्णय किया कि इन समितियों को समाप्त करके इन के अनुसंधान कार्य को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के साथ मिला दिया जाए तथा परिषद् का उपयुक्त पुनर्गठन करके इसे अधिक सुदृढ़ किया जाए जिससे कि परिषद् देश की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि के राष्ट्रीय कार्यक्रम का संचालन तथा विकास कर सके। तदनुसार 30 सितम्बर, 1965 को भारतीय केन्द्रीय मसाले और काजू समिति का विघटन किया गया तथा इसके अनुसंधान कार्यों का भार 1 अक्तूबर, 1965 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने संभाल लिया।

2. समिति द्वारा किए जाने वाला विकास तथा विपणन कार्य भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। मसाले विकास से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क बनाए रखने तथा उनकी सलाह का लाभ प्राप्त करते रहने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारतीय मसाला विकास परिषद् बनाने का निश्चय किया। प्रारम्भ में इस विकास परिषद् का गठन इस प्रकार होगा :—

1. **अध्यक्ष**	निदेशक, काजू विकास प्रादेशिक कार्यालय, (काजू विकास) कोझीकोडे।
2. **उपाध्यक्ष**	श्री पी० बी० कुरूप, मैनेजिंग डायरेक्टर, टैकनो-केमीकल इन्डस्ट्रीज लि०, पोस्ट बा० नं० 74, कोझीकोडे।
3. **सदस्य-गण**	
(क) **केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि**	(क) प्रत्येक राज्य के कृषि विभाग द्वारा मनोनीत निम्नलिखित सरकारों के प्रतिनिधि : (1) केरल (2) मद्रास (3) मैसूर (4) आन्ध्र प्रदेश (5) महाराष्ट्र (6) प० बंगाल (7) असम (8) उड़ीसा (2) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि। (3) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि। (4) कृषि उत्पादन आयुक्त : (5) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अथवा उनके प्रतिनिधि।
(ख) **उत्पादकों के प्रतिनिधि।**	(1) श्री के० टी० थामस, एम० एल० ए० एडवोकेट, करिप्पा परम्बिल, कंजीरापल्ली, केरल राज्य।

(2) श्री सी० ए० मंडाना, एडवोकेट तथा काफी तथा इलायची प्लांटर, मरकारा, जि० कुर्ग, मैसूर ।

(3) श्री डब्ल्यू० पी० ए० आर० नागाराजन, प्लांटर, पट्टीवीरनपट्टी, जि० मदुरा, मद्रास ।

(4) श्री पी० रमना रेड्डी बी० ए० मंटापम्पल्ली, जि० कुडप्पाह, आन्ध्र प्रदेश ।

(5) श्री एन० जी० पोलमो, हमबस्ती, पोस्ट० तकदेब, जि० दार्जिलिंग, पं० बंगाल ।

(6) श्री एच० एस० हुलप्पा, प्लांटर, अनामहल स्टेट, पोस्ट० सकलासपुर, जि० हसन, मैसूर राज्य ।

(7) श्री वी० बी० नारायण राव, वर्धा भवन, वर्धावारी स्ट्रीट, बरहामपुर (जि० गंजम) उड़ीसा राज्य ।

(ग) **व्यापार एंव उद्योग के प्रतिनिधि**

(1) श्री वी० एम० पटेल, अध्यक्ष, भारतीय काली मिर्च तथा मसाले व्यापार संघ कोचीन-2 (केरल राज्य) ।

(2) श्री टी० डी० मैथ्यू, मैसर्ज टी० डी० मैथ्यू एण्ड कं० कोट्टायम, केरल राज्य ।

(3) श्री बी० एल० कजारिया, 28, अमरटोला, स्ट्रीट, कलकत्ता-1, पं० बंगाल ।

(4) श्री एस० बी० शंकर, "वृन्दा", वल्लभ भाई रोड, पोस्ट० तालाकुलम, जि० मदुरा, मद्रास राज्य ।

(घ) **संसद के प्रतिनिधि**

(1) श्री एम० पी० स्वामी, एम० पी० 81, नार्थ एवेन्यू नई दिल्ली-1 ।

(2) श्री पी० अब्राहिम, एम० पी०, 183, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-1 ।

(ङ) **अन्य**

(1) केन्द्रीय खाद्य टैकनालाजीकल अनुसंधान संस्थान, चैलुवम्बा, मैन्शन, मैसूर, का एक प्रतिनिधि।

(2) अध्यक्ष, मसाले निर्यात विकास परिषद्, "निर्यात भवन", महात्मा गांधी रोड, अर्नाकुलम-6 ।

(च) ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति, जिनको समय समय पर सरकार मनोनीत करेगी, जो उन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनका परिषद् में कोई प्रतिनिधि नहीं है ।

4. **सदस्य-सचिव** खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) में मसालों की फसल के कार्य से सम्बन्धित उप-सचिव अथवा कोई अधिकारी ।

5. **प्रेक्षक** (जो कि परिषद् के सदस्य तो नहीं होंगे परन्तु परिषद् के विचार-विमर्श में सहायतार्थ अनिवार्यतः उन्हें आमंत्रित किया जायेगा) ।

(1) कृषि विपणन सलाहकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) ।

(2) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय से सम्बन्धित संयुक्त सचिव (वित्त) ।

(3) अर्थ तथा सांख्यिकीय सलाहकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय, (कृषि विभाग) ।

(4) अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम ।

(5) भारतीय रेलों का एक प्रतिनिधि ।

(6) निदेशक (सुपारी तथा मसाला विकास), प्रादेशिक कार्यालय (सुपारी तथा मसाला विकास), कोझीकोडे ।

3. परिषद् एक सलाहकार संस्था होगी तथा उसके कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए मसालों के विकास के कार्यक्रमों पर समय समय पर विचार करना ।

(2) निर्धारित लक्ष्यांकों के संदर्भ में मसालों के विकास की प्रगति पर पुनरीक्षण तथा उस पर विचार करना ।

(3) मसाला विकास कार्यक्रमो/परियोजनाओं की प्रगति को जहां कहीं आवश्यक हो, तीव्रतर करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिशें करना ।

(4) मसाला विपणन तथा व्यापार की समस्याओं (मूल्य नीति निर्धारण सहित) का पुनरीक्षण एवं उन पर विचार करना तथा उन में सुधार के लिये सुझाव देना, और

(5) भारत सरकार द्वारा समय समय पर परिषद् को सौपा जाने वाला कोई अन्य कार्य ।

4. मसाला उत्पादक क्षेत्रों में व्यापार तथा उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में परिषद् समय समय पर अपनी बैठक बुलाएगी तथा सरकार को अपनी सिफारिशें पेश करेंगी ।

आदेश

आदेश है कि इस संस्ताव की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्री मंडल के सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जायें ।

2. यह भी आदेश है कि यह संस्ताव भारतीय राजपत्र मे जन-साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाये ।

एम० जे० मजूमदार, अपर सचिव

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 1966

विषय.—राष्ट्रीय ग्राम उच्च शिक्षा परिषद की स्थायी समिति का गठन और सदस्यता

सं० एफ० 1-4/66-यू० 3—संकल्प स० एफ० 3-12/55-डी० 6 (आर० एच० ई०) दिनांक 3-2-1956 अधिसूचना सं० एफ० 3-39/56-डी० 6 (आर० एच० ई०) दिनांक 1-5-1956 द्वारा यथा संशोधित के पैराग्राफ 5(क) में आंशिक संशोधन के रूप में भारत सरकार ने निर्णय किया है कि राष्ट्रीय ग्राम उच्च शिक्षा परिषद की स्थायी समिति में 9 सदस्य होंगे । संशोधित पैराग्राफ 5(क) निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा:—

"परिषद एक स्थायी समिति का गठन करेगी जिसके अधिकतम 9 सदस्य होंगे जिनमे उपाध्यक्ष, सचिव, वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि तथा अध्यक्ष द्वारा सदस्यों मे से ही नामजद 6 सदस्य शामिल होंगे । यह समिति परिषद् की प्रमुख कार्यकारी तथा सलाहकार संस्था होगी और इसके वही कार्य तथा अधिकार होंगे जो इसे परिषद द्वारा सौंपे गए हों । परिषद का उपाध्यक्ष स्थायी समिति का अध्यक्ष होगा ।"

2. भारत सरकार ने अब स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है, जो निम्न प्रकार गठित होगी तथा इसकी अवधि इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की होगी:—

1. श्री प्रेम कृपाल — अध्यक्ष
 सचिव (शिक्षा)
 शिक्षा मंत्रालय और उपाध्यक्ष
 राष्ट्रीय ग्राम उच्च शिक्षा परिषद् ।

2. श्री डी० के० हिंगोरानी, — सचिव
 उप शिक्षा सलाहकार,
 शिक्षा मंत्रालय और सदस्य राष्ट्रीय
 ग्राम उच्च शिक्षा परिषद् ।

3 श्री एस० पी० महना,
 उप वित्त सलाहकार,
 वित्त मंत्रालय
 नई दिल्ली ।

नामजद सदस्य

4. श्री जी० रामचन्द्रन,
 संसद सदस्य,
 अवैतनिक निदेशक,
 गांधीग्राम ग्राम संस्थान,
 गांधीग्राम ।

5. श्री टी० एस० अविनाशलिंगम,
 अवैतनिक निदेशक,
 श्रीरामकृष्ण मिशन विद्यालय,
 ग्राम संस्थान,
 कोयम्बतूर ।

6. डा० आर० के० सिंह,
 निदेशक.
 बलवंत विद्यापीठ ग्राम संस्थान
 बिचपुरी (आगरा) ।

7. श्री डी० जे० हतेकर,
 प्रधानाचार्य,
 ग्राम संस्थान.
 वर्धा ।

8. श्री के० एल० बोड़िआ,
 निदेशक, विद्या भवन,
 ग्राम संस्थान,
 उदयपुर ।

9. श्री एस० के० मुखर्जी,
 उप कृषि आयुक्त (शिक्षा),
 खाद्य, कृषि और सामुदायिक विकास मंत्रालय,
 (कृषि विभाग),
 नई दिल्ली ।

जी० के० चन्दीरमानी, अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1966

सं० एफ० 1-2/65-पी० ई० 2—शिक्षा मंत्रालय की 19 मार्च 1966 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में

श्री एम० एम० सुन्द्रा,
संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली ।

को श्री के० एन० चक्रा के स्थान पर अभी से तथा 15 जुलाई 1967 तक अखिल भारतीय खेल परिषद के एक सदस्य के रूप में नामजद किया जाता है ।

रोशन लाल आनन्द, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 1966

सं० 14/3/65-सी०-5—शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 14/3/65 सी०-5 दिनांक 11 अप्रैल 1966 के क्रम में, निम्नलिखित व्यक्ति 4 अप्रैल 1966 से 5 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय इतिहास अभिलेख आयोग के साधारण सदस्य के रूप में नियुक्त किया गए हैं :—

क—साधारण सदस्य

(i) संघटन के पैरा 3-I क(5) के अधीन

1. मद्रास — श्री जी० विक्टर सोलोमन, क्यूरेटर,
 मद्रास रिकार्ड आफिस, मद्रास ।

2. उत्तर प्रदेश — डा० जी० एन० सलेटोर,
 अभिलेखागार-रक्षक
 राज्य अभिलेखागार, उत्तर प्रदेश,
 महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद ।

(ii) संघटन के पैरा 3-I क(6) के अधीन

1. बिहार विश्व-विद्यालय — डा० एच० आर० धौसाल,
 विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व इतिहास विभाग के अध्यक्ष, बिहार विश्वविद्यालय,
 एल० एस० कालेज, मुजफ्फरपुर ।

2. गोरखपुर विश्व-विद्यालय	डा० एच० एस० श्रीवास्तव, एम०ए०, पी०एच०डी०, मध्ययुगीन इतिहास के प्राध्यापक, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ।	
3. उसमानिया विश्वविद्यालय	डा० पी० सारन, इतिहास के प्रोफेसर, उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-7 ।	
4. पटना विश्वविद्यालय	डा० वी०ए० नरेन, एम०ए०, पी०एच०डी, इतिहास विभाग के प्रमुख, पटना कालेज, पटना ।	

(iii) **संघटन के पैरा 3-I (क) (7) के अधीन**

1. बंग साहित्य परिषद्, कलकत्ता	डा०रमेश चन्द्र मजुमदार, बंग साहित्य परिषद् 243/1 आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कलकत्ता-6 ।
2. ऐतिहासिक यूनिट, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	डा० एस० एन० प्रसाद, कार्यभारी अधिकारी, इतिहास सम्बन्धी अनुभाग, रक्षा मंत्रालय, प्रदर्शनी ग्राउंड, मथुरा रोड, नई दिल्ली ।
3. कामरूप अनुसंधान समिति, गोहाटी, (आसाम)	डा० प्रफुल्लदत्त गोस्वामी, एम०ए०, डी० फूले, संयुक्त सचिव, कामरूप अनुसंधान समिति, अंग्रेजी विभाग, गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी (आसाम) ।

टी० एस० कृष्णमूर्ति, उप सचिव

भारतीय भाषा समिति

संकल्प

नई दिल्ली-2 दिनांक 28 अप्रैल 1966

[शिक्षा मंत्रालय के संकल्प सं० 8-1/65-एस०यू०, दि० 15 फरवरी 1966 के स्थान पर]

सं० एफ० 8-1/65—एस० यू०—सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के महत्व और केन्द्र की राजकीय भाषा से उनके सहज संबंध को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने "भारतीय भाषा समिति" नामक एक सलाहकार समिति स्थापित करने का निर्णय किया है।

2. यह निश्चय किया जाता है कि भारतीय भाषा समिति (इसके बाद समिति कहलाएगी) का गठन और कार्य तथा उसकी अवधि इस प्रकार होगी :—

(अ) **समिति का गठन** :

अध्यक्ष	(क) शिक्षा मंत्री
उपाध्यक्ष	(ख) शिक्षा मंत्रालय के भाषा प्रभाग का कार्यभारी मंत्री ।
सदस्य	(ग) प्रत्येक राज्य सरकार का एक-एक प्रतिनिधि जो भारतीय भाषाओं से सम्बन्धित अधिकारी हो और उप-सचिव अथवा शिक्षा निदेशक के पद से कम का न हो।
	(घ) अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा मनोनीत लोक सभा के चार सदस्य ।
	(ङ) सभापति, राज्य सभा द्वारा मनोनीत राज्य सभा के दो सदस्य ।
	(च) संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित चौदह भाषाओं के एक-एक प्रमिख विद्वान अथवा लेखक जिन्हें भारत सरकार नामजद करेगी ।
	(छ) विशिष्ट क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम 6 व्यक्ति जो भारत सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे ।
	(ज) अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ।
	(झ) अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का स्थायी आयोग ।
	(ञ) निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ।
	(त) सचिव, साहित्य अकादेमी ।
	(थ) गृह मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।
	(द) शिक्षा मंत्रालय के भाषा प्रभाग का कार्यभारी संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार; और
	(ध) भाषा प्रभाग का कार्यभारी उप शिक्षा सलाहकार (उप सचिव) ।

(आ) **समिति के कार्य**

समिति आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास और संघ की भाषा से उनके संबंध विषयक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देगी ।

(इ) **अवधि**

समिति के सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की कार्यविधि तीन वर्ष होगी बशर्ते :—

(i) (ग) और (थ) में उल्लिखित सदस्यों के संबंध में तत्संबंधी राज्य सरकारें अथवा गृह मंत्रालय, जो भी संबंधित हों, यदि चाहें तो अपने प्रतिनिधियों को तीन वर्ष के कार्यकाल से पहले भी बदल सकते हैं ;

(ii) लोकसभा एवं राज्य सभा का प्रतिनिधि सदस्य लोक सभा एवं राज्यसभा का सदस्य न रहने पर समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा ;

(iii) भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य भारत सरकार के प्रसाद पर्यन्त ही समिति के सदस्य रहेंगे ;

(iv) (ज), (झ), (ञ), (त), (द) एवं (ध) में उल्लिखित सरकारी सदस्य तभी तक इस समिति के सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर आसीन रहें जिसके कारण कि वे इस समिति के सदस्य बने हैं ;

(v) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त हो तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य उक्त सदस्य की शेष कार्यविधि तक ही सदस्य रहेगा ।

3. सभी नामित सदस्यों का कार्यकाल संबंधित वित्त वर्ष की पहली जून से प्रारम्भ हुआ माना जाएगा सिवाय 3 (v) में उल्लिखित सदस्यों के जिनका कार्यकाल उनके नामन की तिथि से प्रारम्भ होगा ।

4. समिति अपने कार्यों के समुचित सम्पादन के लिए यथावश्यक उप-समितियां नियुक्त कर सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और केन्द्रीय प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

परमेश्वर दीन, संयुक्त शिक्षा सलाहकार

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-1, the 30th April 1966

No. 3(1)*ECI*/66.—The following members of the Lok Sabha have been elected to serve on the Committee on Estimates for the term beginning on the 1st May, 1966 :

1. Shri A. Shanker Alva.
2. Shri Onkarlal Berwa.
3. Shri Dinen Bhattacharya.
4. Shri Purushottamdas Haribhai Bheel.
5. Sardar Daljit Singh.
6. Dr. Mono Mohan Das.
7. Shri Digambar Singh Chaudhri.
8. Shri Arun Chandra Guha.
9. Shri Kashi Ram Gupta.
10. Shri J. N. Hazarika.
11. Shrimati Jamuna Devi.
12. Shri Narayan Sadoba Kajrolkar.
13. Shri C. M. Kedaria.
14. Shri Baij Nath Kureel.
15. Shrimati Sangam Laxmi Bai.
16. Shri Rama Chandra Mallick.
17. Shri Dwarka Dass Mantri.
18. Shri Dhuleshwar Meena.
19. Shri Mohan Swarup.
20. Shri T. D. Ramabadran.
21. Shri J. Ramapathi Rao.
22. Shri Rameshwar Sahu.
23. Dr. Ranen Sen.
24. Shri M. Shankaraiya.
25. Shri Nardeo Snatak.
26. Shri N. M. R. Subbaraman.
27. Shri Shiva Datt Upadhyaya.
28. Shri Virbhadra Singh.
29. Shri Vishram Prasad.
30. Shri Bhishma Prasad Yadava.

The 3rd May 1966

No. 3(1)*ECI*/66.—The Speaker has been pleased to appoint Shri Arun Chandra Guha as Chairman of the Committee on Estimates for the term beginning on the 1st May 1966.

AVTAR SINGH RIKHY, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 22nd April 1966

Committee on Technical Consultancy Services

No. I&M-4(9)/2/66.—Consequent on demise of Shri K. L. Ghei, a member of the Committee on Technical Consultancy Services constituted under Planning Commission Resolution No. I&M-4(9)/2/66 dated 9th February 1966, Shri T. Swaminathan, Secretary, Deptt. of Defence Supply, is appointed, with immediate effect, as a member of the Committee *vice* Shri K. L. Ghei.

D. DAS, Under Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 25th April 1966

No. 25/65-*ITD.*—The Committee for Studies on Economic Development in India and Japan, which was set up *vide* Planning Commission Resolution No. F.13(39)/62-ADM.I dated the 1st June, 1962, has been reconstituted as follows :—

Chairman

Prof. V. K. R. V. Rao

Members

Shri Lalji Mehrotra.

Shri Ramnath A. Podar.

Dr. D. K. Ghosh, Chief of Division, Planning Commission will be the Secretary of the Committee.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, all Chief Ministers of States, all Ministries of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President and heads of all Indian Missions abroad

ORDERED also that a copy be published in the Gazette of India.

K. A. P. STEVENSON, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

RESOLUTIONS

New Delhi, the 28th April 1966

No. 34(4)/65-*L.Ind.II.*—Government of India have decided to set up a Panel for the Glass and Ceramics Industries. The tenure of the Panel will be two years from the date of this Resolution and its composition will be as follows :—

Chairman

1. Dr. S. R. Lele,
M/s Borosil Glass Works Ltd.,
Chotani Estates, Proctor Road,
Grant Road, Bombay-7.

Members

2. Shri G. K. Bhagat,
M/s. Bengal Potteries Ltd.,
45, Tangra Road, Calcutta-15.
3. Shri M. K. Ganpule,
M/s. Parshuram Pottery Works Co. Ltd.,
Mankaner, (Gujarat).
4. Shri H. L. Somany,
M/s. Hindusthan Twyfords Ltd.,
Post Box No. 990,
Calcutta-1.
5. Shri A. Samba Moorty,
Director,
Government Porcelain Factory,
Bangalore-12.
6. Shri S. K. Bose,
Geologist (Sr.),
Geological Survey of India,
27, Chowringhee Road,
Calcutta-13.
7. Shri K. D. Sharma,
Scientist,
Central Glass and Ceramic Research Institute,
Calcutta-32.
8. Shri B. B. Sarkar,
Krishna Silicate & Glass Works Ltd.,
6, Ezra Street, Calcutta-1.
9. Shri V. R. Bhide,
M/s. Kangam Private Ltd.,
208, Lady Jamshedji Road,
Bombay-16.
10. Shri P. C. Varshney,
M/s. Soraikella Glass Works (Private) Ltd.,
Kandra, (Singhbhum),
Bihar.
11. Shri C. G. Amin,
Director (Manufacturing),
M/s. Alembic Glass Industries Ltd.,
Alembic Road, Baroda.
12. Shri K. H. Parikh,
General Manager,
Vibhuti Glass Factory,
Ramnagar, Varanasi, (U.P.).
13. Development Officer, (Ceramics),
Directorate General of Technical Development,
Udyog Bhavan, New Delhi.

Member-Secretary

14. Shri S. R. Khanna,
Development Officer (Glass),
Directorate General of Technical Development,
Udyog Bhavan, New Delhi.

2. The functions of the Panel would be :—

(i) To make a detailed assessment of raw material requirements and to explore ways and means of establishing agencies for standardised raw materials for glass and ceramic industries and to make assessment of requirements of machinery/spare parts for the glass and ceramic industries with a view to encouraging their production.

(ii) To suggest norms of efficiency with a view to eliminating wastage of fuel and raw materials, obtaining maximum production, improving quality and reducing costs.

(iii) To recommend measures for securing the fuller utilisation of the installed capacity and for improving the working of the industry, particularly of the less efficient units.

(iv) To make a vigorous attempt to take up an export programme, especially for items which have a surplus capacity.

(v) To investigate possibilities of production of items which can be taken up by allied industries.

(vi) To establish a suitable machinery for ensuring steady development in the field of training technical personnel.

(vii) To suggest ways and means for import substitution of raw materials spares and other connected equipment.

(viii) To advise on any matter relating to the industry on which the Central Government may request the Panel to advise and undertake enquiries for the purpose of enabling the Panel to so advise.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 29th April 1966

No. 34(4)/65-*L.IndII.*—Government of India have decided o set up a Panel for Refractory Industry. The tenure of the 'enal will be two years from the date of this Resolution and ts composition will be as follows :—

Chairman

1. Shri D. R. Subramanian,
General Manager,
M/s. Burn & Co. Ltd.,
12, Mission Row,
Calcutta-1.

Members

2. Dr. S. P. Varma,
Industrial Adviser,
Directorate General of Technical Development,
Udyog Bhavan, New Delhi.
3. Shri J. C. Banerjee,
Scientist,
Central Glass and Ceramic Research Institute,
Calcutta-32.
4. Dr. B. N. Sinha,
Geologist (Sr.),
Geological Survey of India,
27, Chowringhee Road, Calcutta-13.
5. Shri M. Satyapal,
Director (Chemicals),
Planning Commission, New Delhi.
6. Dr. S. S. Ghose,
Chief Superintendent,
(Iron & Steel),
Hindustan Steel Limited,
Bhilai Steel Plant,
Bhilai (Madhya Pradesh).
7. Shri K. P. Jhunjhunwala,
M/s. Orissa Industries Ltd.,
Barang, District Cuttack,
Orissa.
8. Shri P. R. Chaki,
M/s. Belpahar Refractories Ltd.,
Belpahar, Orissa.
9. Shri M. H. Dalmia,
M/s. Orissa Cement Ltd.,
Rajgangpur, Orissa.
10. Shri B. N. Bhaskar,
Managing Director,
M/s. The Ishwar Industries Ltd.,
Ishwar Nagar, New Delhi.

Member-Secretary

11. Development Officer (Ceramics),
Directorate General of Technical Development,
Udyog Bhavan, New Delhi.

2. The functions of the panel would be :—

(i) to make a detailed assessment of the pattern of demand for the various types of refractories as dependent on the pattern of steel production during the Fourth Five Year Plan as well as for meeting the requirements of other industries.

(ii) to suggest ways and means for import substitution of raw materials, spares and other connected equipment;

(iii) to suggest norms of efficiency with a view to eliminating wastage of fuel and raw materials, obtaining maximum production, improving the quality and reducing costs;

(iv) to advise on any matters relating to the industry on which the General Government may request the Panel to advise and undertake enquiries for the purpose of enabling the Panel to so advise.

(v) to engage itself in a vigorous attempt to take up an export programme especially for some of the types of refractories which have become surplus in India (like silica refractories) due to changes in the process of steel-making;

(vi) to establish a suitable machinery for ensuring steady development in the field of training technical personnel; and

(vii) to assess the extent to which diversification in the present manufacturing range is to be undertaken consequent on fall and increase in the consumption of certain types of refractories.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. K. RANGAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF IRON AND STEEL

ORDER

New Delhi, the 29th April 1966

No. SC(I)-24(42)/65.—In the Order of the Government of India in the Ministry of Iron and Steel No. SC(I)-24(42)/65 dated the 20th April, 1966 published in the Part I, Section 1 of the Gazette of India dated the 30th April, 1966, the following may be added to the list of members :—

One representative of the Engineering Association of India, India Exchange (8th Floor), India Exchange Place, Calcutta-1.

CORRIGENDUM

*No. SC(I)*24(42)/65.—In the Resolution of the Government of India in the Ministry of Iron and Steel No. SC(I)-24(42)/65 dated the 20th April, 1966 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated the 30th April, 1966, in sub-para (iii) of para 2 :—

FOR "Twenty-six members".

READ "Twenty-seven members".

ORDER

ORDERED that a copy of this may be published in the Gazette of India for general information.

P. P. CAPRIHAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

RESOLUTION

New Delhi, the 5th May 1966

*No. F.*12-28/63-*FP.II.*—In partial modification of this Ministry's Resolution No. F.12-28/63-FP.II dated the 20th January, 1966 regarding constitution etc. of the Family Planning Programme Evaluation and Planning Committee, it has now been decided that the Committee will submit their report by the 31st July, 1966 instead of the 31st March, 1966.

ORDER

ORDERED that copy of the Resolution be communicated to :—

1. Dr. Sushila Nayar,
Minister for Health & Family Planning,
Government of India, New Delhi.
2. Smt. Dhanvanti Rama Rau,
President, International Planned Parenthood Federation C/o Family Planning Association of India,
1, Metropolitan House, Dada Bhai Naroji Road,
Bombay.
3. Dr. (Smt.) Soundaram Ramachandaran,
Deputy Minister for Education,
Government of India, New Delhi.
4. Dr. P. D. Bhave, Director of Public Health,
Maharashtra, Poona.
5. Dr. (Mrs.) S. L. Talwar,
Assistant Director (F.P.),
Uttar Pradesh, Lucknow.
6. Smt. Avabai B. Wadia,
President, Family Planning Association of India,
1, Metropolitan House,
Dadabhai Naroji Road, Bombay.
7. Smt. Renuka Ray, M.P.,
187, South Avenue,
New Delhi.
8. Shri Thirumal Rao, M.P.,
3, Electric Avenue,
New Delhi-1.
9. Shri B. Mukherjee,
Secretary, Ministry of Health & Family Planning,
(Deptt. of Health), Patiala House, New Delhi.
10. Dr. V. R. Khanolkar,
Chairman, Advisory Committee on Scientific Aspects of Family Planning of the I.C.M.R.,
Indian Cancer Research Centre,
Parel, Bombay-12.
11. Shri S. P. Jain,
Director, Demographic Training and Research Centre,
Chembur, Bombay-71.
12. Shri K. A. P. Stevensen,
Joint Secretary (P.C.),
Planning Commission,
Yojna Bhavan, New Delhi.
13. Lieut. Colonel Barkat Narain,
Adviser (Health), Ministry of Community Development, Panchayati Raj and Cooperation,
Krishi Bhavan, New Delhi.
14. Col. M. Shankhla,
Director of Medical Institute,
Directorate of Technical Development,
Ministry of Commerce & Industry, New Delhi.

15. Shri N. Chidambaran,
Deputy Secretary, Ministry of Commerce & Industry,
New Delhi.

16. Shri M L. Bhardvaj,
Director of Advertising & Visual Publicity,
Curzon Road Barracks, New Delhi.

17. Shri Ashok Mitra,
Registrar General (India),
Kotah House Annexe, 2-A Man Singh Road,
New Delhi-11.

18. Dr. A. B. Kar,
Assistant Director General,
Drugs Research Institute, Lucknow (U.P.).

19. Representative,
Central Statistical Organisation,
Yojna Bhawan, New Delhi.

20. Lieut. General S. P. Bhatia,
Commissioner, Family Planning,
Patiala House, New Delhi.

21. Lieut. Col. B. L. Raina,
Director, Central Family Planning Institute,
L-17, Green Park, New Delhi.

22. Shri Govind Narain,
Secretary, Ministry of Health & Family Planning,
(Department of Family Planning),
Patiala House, New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. P. ATRI, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

(I.C.A.R.)

RESOLUTIONS

New Delhi-1, the 29th April 1966

No. 1.6-5 65-Reorgn.(CC)(Admn.).—The Second Joint Indo-American Team, appointed in 1959, to review the position of Agricultural Education, Research and Extension in India, recommended that in the interest of consolidating the Central Agricultural Research Programme and assuring adequate coordination, all Central Institutes and Commodity Committees should be brought under the full technical and administrative control of the Indian Council of Agricultural Research. This recommendation was strongly supported by the Agricultural Research Review Team, appointed in 1963. The Government of India have examined the above recommendations in the light of the actual functioning of the Central Commodity Committees during the past years and recently decided that the Commodity Committees should be abolished and the research work being conducted by them be integrated with the Indian Council of Agricultural Research, which should be suitably reorganised and strengthened, so as to enable it to develop and administer a National Programme of Agricultural Research, commensurate with the needs of the country. Accordingly, the Indian Central Spices and Cashewnut Committee was dissolved on the 30th September, 1965 and its research activities have been assumed by the Indian Council of Agricultural Research, with effect from the 1st October, 1965.

2. The Government of India have taken over the development and marketing functions handled by the Committee. In order to continue the association of the various official and non-official interests with the development of cashewnut and have the benefit of their continued advice, the Government of India have decided to constitute an Indian Cashewnut Development Council. To begin with, the Council will consist of the following :—

1. *Chairman*

Director, Cashewnut Development,
Regional Office, (Cashewnut Development),
Kozhikode.

2. *Vice-Chairman*

Shri C. M. John,
"Cherukara", Changanachery P.O.,
Kerala State.

3. *Members*

(a) *Representatives of the Central and State Governments*

(1) One representative each of the State Department of Agriculture to be nominated by the Governments of
(i) Kerala,
(ii) Madras,
(iii) Mysore,
(iv) Andhra Pradesh,
(v) Orissa,
(vi) West Bengal,
(vii) Maharashtra,
(viii) Assam.

(2) One representative of the Planning Commission.

(3) One representative of the Ministry of Commerce.

(4) Director General, Indian Council of Agricultural Research or his representative.

(5) Agricultural Production Commissioner.

(6) Chairman, Cashew Export Promotion Council.

(b) *Growers' representatives*

(1) Shri A. B. Prabhu, B.Sc.(Agri.) LL.B., Sawantwadi, District Ratnagiri, Maharashtra.

(2) Shri Omeo Kumar Das, M.L.A., Dhekiajuli, Darrang, Assam.

(3) Shri V. B. Narayana Rao, Vardha House, Vardhavari Street, Berhampur (Ganjam District), Orissa State.

(4) One representative from Kerala.

(5) One representative from Mysore.

(c) *Such additional persons, as may from time to time, be*

(1) Shri S. M. Thaha,
C o Musahiar Industries Ltd.,
Quilon, Kerala State.

(2) Shri V. P. Varde,
C/o R R. Nabar & Company,
P.O. Box No. 1498, Dalal Street,
Fort, Bombay.

(3) Shri Sitam Radhakrishniah,
President,
Palasa Cashew Manufacturers'
Association, Palasa,
Srikakulam District Andhra Pradesh.

(4) Shri Vittaldas Shetty Vittal,
Mangalore, South Kanara District,
Mysore.

(d) *Representative of Parliament*

Shri Cherian J. Kappen, M.P.,
177, North Avenue,
New Delhi.

(e) *Such additional persons, as may from time to time, be nominated by the Government of India, to represent interests not already represented in the Council.*

4. *Member-Secretary*

Deputy Secretary or any other officer dealing with the crop in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).

5. *Observers*

(who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

(1) Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, (Department of Agriculture).

(2) Joint Secretary (Finance) accredited to the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation.

(3) Economic & Statistical Adviser, Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Department of Agriculture).

(4) Chairman, State Trading Corporation.

(5) A representative of Railways.

3. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) to consider, from time to time, the cashewnut development programmes formulated by the Central and State Governments;

(ii) to consider and review the progress of cashewnut development in the context of targets laid down;

(iii) to recommend measures for accelerating the tempo of development programmes/schemes, wherever necessary;

(iv) to consider and review the problems of cashewnut marketing and trade, including price policy, and to make suggestions for improvement; and

(v) any other function, which may from time to time, be assigned by the Government of India to the Council.

4. The Council will meet periodically in important centres of trade and industry, in areas in which cashewnut is grown and will make its recommendations to the Goverment of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and the Departments of the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat,

Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. 6-6/65-Reorgn.(CC)(Admn.).—The Second Joint Indo-American Team, appointed in 1959, to review the position of Agricultural Education, Research and Extension in India, recommended that in the interest of consolidating the Central Agricultural Research Programme and assuring adequate coordination, all Central Institutes and Commodity Committees should be brought under the full technical and administrative control of the Indian Council of Agricultural Research. This recommendation was strongly supported by the Agricultural Research Review Team, appointed in 1963. The Government of India have examined the above recommendations in the light of the actual functioning of the Central Commodity Committees during the past years and recently decided that the Commodity Committees should be abolished and the research work being conducted by them be integrated with the Indian Council of Agricultural Research, which should be suitably reorganised and strengthened, so as to enable it to develop and administer a National Programme of Agricultural Research, commensurate with the needs of the country. Accordingly, the Indian Central Spices and Cashewnut Committee was dissolved on 30th September, 1965 and its research activities have been assumed by the Indian Council of Agricultural Research, with effect from 1st October, 1965.

2. The Government of India have taken over the development and marketing functions handled by the Committee. In order to continue the association of the various official and non-official interests with the development of spices and have the benefit of their continued advice, the Government of India have decided to constitute an Indian Spices Development Council. To begin with, the Council will consist of the following :—

1. *Chairman*

Director, Cashewnut Development,
Regional Office (Cashewnut Development),
Kozhikode.

2. *Vice-Chairman*

Shri P. B. Kurup,
Managing Director,
Techno Chemical Industries Ltd.,
P.O. Box No. 74, Kozhikode.

3. *Members*

(a) *Representatives of the Central and State Governments*

(1) One representative each of the State Department of Agriculture to be nominated by the Governments of

(i) Kerala.
(ii) Madras.
(iii) Mysore.
(iv) Andhra Pradesh.
(v) Maharashtra.
(vi) West Bengal.
(vii) Assam.
(viii) Orissa.

(2) One representative of the Planning Commission.

(3) One representative of the Ministry of Commerce.

(4) Agricultural Production Commissioner.

(5) Director General, Indian Council of Agricultural Research or his representative.

(b) *Growers' representatives*

(1) Shri K. T. Thomas, M.L.A.,
Advocate, Karippaparambil, Kanjirapally,
Kerala State.

(2) Shri C. A. Mandana,
Advocate and Coffee & Cardamon Planter, Mercara.
Coorg District, Mysore State.

(3) Shri W. P. A. R. Nagarajan,
Planter, Pattiveeranpatti, Madurai District,
Madras State.

(4) Shri P. Ramana Reddy, B.A.,
Mantapampally, Cuddappah District,
Andhra Pradesh.

(5) Shri N. G. Yolmo,
Humbusty, P.O. Takdeb, District Darjeeling,
West Bengal.

(6) Shri H. S. Halappa,
Planter, Anemahal Estate, Saklaspur P.O., Hassan District, Mysore State.

(7) Shri V. B. Narayana Rao,
Vardha House, Vardhavari Street, Berahampur,
(Ganjam District), Orissa State.

(c) *Representatives of Trade and Industry*

(1) Shri V. M. Patel,
President,
Indian Pepper & Spices Trade Association,
Cochin-2 (Kerala State).

(2) Shri T. D. Mathew,
M s. T. D. Mathew & Company, Kottayam,
Kerala State.

(3) Shri B. L. Kajaria,
28, Amratolla Street, Calcutta-1 (West Bengal).

(4) Shri S. B. Sankar,
"Brinda" Vallabhai Road, Tallakulam P.O.,
Madurai District, Madras State.

(d) *Representatives of Parliament*

(1) Shri M. P. Swamy, M.P.,
91, North Avenue,
New Delhi.

(2) Shri P. Abraham, M.P.,
193, North Avenue,
New Delhi.

(e) *Others*

(1) A representative of the Central Food Technological Research Institute, Chaluvamba Mansion, Mysore.

(2) Chairman, Spices Export Promotion Council,
"Export House", Mahatma Gandhi Road,
Ernakulam-6.

(f) *Such additional persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India, to represent interests not already represented in the Council*

4. *Member-Secretary*

Deputy Secretary or any other Officer dealing with the crop in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Department of Agriculture).

5. *Observers*

(who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

(1) Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).

(2) Joint Secretary (Finance) accredited to the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation.

(3) Economic & Statistical Adviser, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).

(4) Chairman, State Trading Corporation.

(5) A representative of Railways.

(6) Director (Arecanut & Spices Development), Regional Office (Arecanut & Spices Development), Kozhikode.

3. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) to consider, from time to time, the Spices Development Programmes formulated by the Central and State Governments;

(ii) to consider and review the progress of Spices Development in the context of targets laid down;

(iii) to recommend measures for accelerating the tempo of development programmes/schemes, wherever necessary;

(iv) to consider and review the problems of spices marketing and trade, including price policy, and to make suggestions for improvement; and

(v) any other function, which may from time to time, be assigned by the Government of India to the Council.

4. The Council will meet periodically in important centres of trade and industry, in areas in which spices are grown and will make its recommendations to the Government of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and the Departments of the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. J. MAJUMDAR, Additional Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

RESOLUTION

BHARATIYA BHASHA SAMITI

New Delhi-1, the 28th April 1966

(To be substituted for the Min. of Edu. Resolution No. 8-1/65-SU, dated 15th February 1966)

No. F.8-1/65-SU.—Considering the importance of development of the various Modern Indian Languages and their intrinsic relationship with the official language of the Union, the Government of India have decided to set up an Advisory Committee called the Bharatiya Bhasha Samiti.

2. It is hereby resolved that the composition, functions and tenure of the Bharatiya Bhasha Samiti (hereinafter referred to as 'Samiti') will be as follows :—

(A) *Composition of the Samiti*

Chairman

(a) Minister of Education.

Vice-Chairman

(b) Minister in charge of the Languages Division in the Ministry of Education.

Members

(c) One representative of each State Government, who should be the officer dealing with Indian languages, and not lower in status than that of either Deputy Secretary or the State Director of Education.

(d) Four members from the Lok Sabha to be nominated by the Speaker of the Lok Sabha.

(e) Two members from the Rajya Sabha to be nominated by the Chairman of the Rajya Sabha.

(f) An eminent scholar or writer in each of the 14 languages, mentioned in the VIII Schedule of the Constitution, to be nominated by the Government of India.

(g) Not more than six persons to be nominated by the Government of India to represent special interests.

(h) Chairman, National Book Trust.

(i) Chairman, Standing Commission for Scientific and Technical Terminology.

(j) Director, Central Hindi Directorate.

(k) Secretary, Sahitya Akademi.

(l) A representative of the Ministry of Home Affairs.

(m) Joint Secretary/Joint Educational Adviser in Charge of the Languages Division, Ministry of Education, and

Secretary

(n) Deputy Educational Adviser/Deputy Secretary in Charge of the Languages Division.

(B) *Functions of the Samiti*

The Samiti will advise the Government of India on all matters relating to the development of Modern Indian Languages and their relationship with the Language of the Union.

(C) *Tenure*

The tenure of the official and non-official members of the Samiti shall be three years, provided that :

(i) in the case of the members at (c) and (l), the Government of the State concerned or the Ministry of Home Affairs, as the case may be, can change its representative, if it so desires, before the expiry of three years;

(ii) a representative of the Lok Sabha or Rajya Sabha shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of the Lok Sabha or Rajya Sabha, as the case may be;

(iii) the members nominated by the Government of India shall hold office during the pleasure of that Government;

(iv) the official members of the Samiti at (h), (i), (j), (k), (m) and (n) shall continue as members, so long as they hold office, by virtue of which they are members of the Samiti; and

(v) if a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death, etc., of a member, the member nominated in that vacancy shall hold office for the residue of the tenure of the member.

3. The tenure of all nominated members will be deemed to commence from 1st of June of the financial year in question, except that of the members covered by C(V), in which case, it will commence from the date of nomination.

4. The Samiti may appoint such committees, as it may deem necessary for the proper discharge of its functions.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Administrations, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. D. SHUKLA, Jt. Educational Adviser

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

RESOLUTION

New Delhi, the 28th April 1966

No. 15/7/65-SCT.II.—The Government of India have appointed Shri Jaipal Singh, M.P. and Shri N. Sri Rama Reddy, M.P., as members of the Central Advisory Board for Tribal Welfare in the vacancies caused by the death of Shri Mahesh Saran, M.P. and appointment of Shri C. M. Poonacha as a Union Minister.

ORDER

ORDERED that the above be published in the Gazette of India.

S. C. SEN GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

GOVERNMENT OF BIHAR

River Valley Projects Department

(TENUGHAT DAM WING)

RESOLUTION

Patna, the 21st April 1966

No. TDP/W1-101/66-824 T.—With a view to ensuring efficient, economical and expeditious execution of the Tenughat Dam Project, and also securing co-ordination amongst the various beneficiaries of the project, the Government of Bihar, in consultation with the Government of India, have agreed to set up a Control Board as described below :—

1. The Control Board will be in overall charge of the project including its technical and financial aspects. The actual work of construction will be carried out by the Government of Bihar.

2. Powers will be delegated to the Chief Administrator, the Chief Engineer, Tenughat Dam Project, and such other staff as may be found necessary, to contract for works, supplies and services at the direction of the Control Board, such contracts to be executed as on behalf of the Government of Bihar.

3. The Tenughat Dam Control Board will consist of the following :—

Chairman

(i) Chief Minister, Bihar.

Members

(ii) Minister for Irrigation and Power, Bihar.

(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Irrigation and Power (or his representative).

(iv) Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) or his representative.

(v) Secretary to the Government of India, Ministry of Steel (or his representative).

(vi) Chairman, Central Water and Power Commission (or his representative).

(vii) Development Commissioner, Bihar.

(viii) Secretary, Finance Department, Bihar.

(ix) Chief Engineer, Tenughat Dam Project, Bihar.

Member-Secretary

(x) Chief Administrator & Secretary to Government, River Valley Projects Department, Bihar.

The financial Adviser-*cum*-Chief Accounts Officer, attached to the River Valley Projects Department; Irrigation Secretary; Secretary, Public Health Engineering Department and Chief Secretary, Bihar will, ordinarily, be invited to attend the meeting of the Board.

The Board shall have the powers to invite to its meetings, such other officers as it may consider necessary.

4. In particular, and without prejudice to the generality of the provisions above, the Board shall :—

(a) scrutinise the estimate of the project, advise necessary modifications and recommend the estimate for administrative approval of the Government of Bihar;

(b) examine and decide all proposals for preparation of designs and for obtaining expert advice;

(c) examine and approve from time to time, the delegation of such powers—technical, financial and administrative as it may deem necessary, for the efficient execution of the project, to the Chief Administrator, Chief Engineer and other officers concerned with the execution of the project;

(d) examine and, where necessary, lay down specifications and schedule of rates for various classes of work with a view to sound and efficient execution of the project;

(e) approve all sub-estimates and contracts, the cost of which exceeds the powers of sanction of the Chief Administrator or the Chief Engineer;

(f) approve all proposals for award of work or supplies on contract other than those based on public tenders, and on detailed quantitative estimates and works allotted on work order basis on schedule rates.

NOTE (1) : Where total financial liability under a contract is definitely ascertainable at the time of placing the contract and where the contract itself is the result of a public or limited call for tenders, prior submission of the proposals to the Control Board will not be necessary so long as the contract is otherwise within the powers of sanction of the Chief Administrator or the Chief Engineer.

NOTE (2) : This will not affect the power delegated from time to time to the Chief Administrator or the Chief Engineer.

(g) decide the programme of construction of different parts of the project, keeping in view the funds available, the economics of the project, and co-ordination of the supply of water, with its requirements;

(h) decide on the programme of resettlement of persons displaced as a result of the project works and scrutinize and recommend expenditure on resettlement;

(i) receive such progress reports as it may prescribe both as to work and expenditure from the Chief Administrator and other officers, review the progress of the project and lay down steps to be taken to expedite the work;

(j) the Board will frame rules as to delegation of power and procedure for the purpose of carrying out its business. It may constitute a Standing Committee and entrust to it such of its functions and delegate to the Committee such of its powers as it may deem fit. The Board may also appoint Sub-Comittees to carry out specific assignments.

B. N. SINHA,

Chief Administrator & Secretary to the Government of Bihar, River Valley Projects Department, Patna.

S. NARAYANASWAMY, Under Secy.

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1966